Reg No 177/2008-2009 ISSN: 2322–0317

PSSH PERSPECTIVE of SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

An International Multidisciplinary Refereed Research Journal

VOL 2, NO 2

JULY - DECEMBER 201

Biannual

Editor

Dr Hemant Kumar Singh

Assistant Professor

Economics Department

Madan Mohan Malviya PG College

Deoria (UP)

Publisher

Herambh Welfare Society

Varanasi (India)

भारत में खाद्य सुरक्षा-एक आर्थिक विश्लेषण

पूनम

भूख, कुपोषण और गरीबी कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, जिनका सामना पूरी दुनिया खासकर विकासशील देश लंबे समय से कर रहे हैं। इनमें से खाद्य सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सबसे ज्यादा चिंताएँ व्यकत की जाती रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सबसे ज्यादा चितांएँ व्यक्त की जाती रही है। क्षेत्रीय स्तर पर चाहे यह सार्क पुड बैंक की बात हो या अंतर्राट्रीय स्तर पर खाद्य एवं कृषि संगठन का सवाल, ये संगठन लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि दुनिया से भूख को मिटाया जा सके और सबको स्वस्थ व पोषणीय आहार उपलब्ध करवाकर खाद्य सुरक्षा के तंत्र को मजबूत व कल्याणकारी बनाया जा सके। यह उचित भी है क्योंकि भले ही कुछ देश या कुछ लोग सम्पन्नता की सीढ़ियाँ चढ़ गए हों लेकिन यह तथ्य है कि आज भी एक बड़ी आबादी बगैर भोजन के रहने को अभिशक्त है।

खाद्य सुरक्षा एक जटिल प्रश्न है परंतु किसी भी देश की उन्नति का पहला स्तंभ यही हैं भारत दुनिया के प्रमुखतम अन्न उत्पादक देशों में गिना जाता हैं परंतु विश्व भूख सूचकांक (2013) में इसका स्थान कुल 120 देशों में से 63वाँ हैं आज भी भारत खाद्य सुरक्षा के स्तर पर विश्व में निचले पायदान पर अवस्थित है।

विश्व खाद्य और कृषि संगठन (F.A.O.) के अनुसार दुनिया के दो क्षेत्रों उपसहारा अफ्रीका और एशिया– प्रशांत क्षेत्र में क्रमशः 256 मिलियन और 642 मिलियन लेसा गरीबी और कुपोषण से अभिशप्त हैं इसी तरह विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2011) के अनुसार दक्षिण एशिया जहाँ दुनिया के आधे से अधिक गरीब बसते है, में 500 मिलियन लोग क्रमशक्ति के आधार पर 1–25 डालर प्रतिदिन से कम पर गुजारा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सदस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में से पहला लक्ष्य वर्ष 2015 तक दुनिया से गरीबी ओर भूख को खत्म करना हैं आज पूरी दुनिया में एक अरब से अधिक लोग गरीबी, भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं। जहाँ तक भारत में गरीबी का प्रश्न है विश्व बैंक की रिपोर्ट (2011) के अनुसार भारत की एक तिहाई आबादी (32.7 प्रतिशत) अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे हैं अर्थात् इनकी प्रति व्यक्ति आमदनी क्रमशक्ति के आधार पर 1–25 डॉलर प्रतिदिन से कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 51–7 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन की आमदनी प्रति व्यक्ति मात्र 2 डॉलर या इससे कम हैं परन्तु भारत के योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत ताला ऑकडें दर्शाते हैं कि भारत में गरीबी

की दर तेजी से घटी है। आयोग के अनुसार 2011–12 में देश में 21.9 प्रतिशत लोग ही गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है।

गरीबी और खाद्य असुरक्षा सही अर्थो में एक–दूसरे के पूरक हैं। परन्तु यहाँ खाद्य असुरक्षा को एक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जा रहा हैं किसी भी देश में केवल गरीब व्यक्ति ही खाद्य असुरक्षा का शिकार नही होता बल्कि वे लोग भी खाद्य असुरक्षित हो सकते हैं जो गरीबी की रेखा से ऊपर हो, यदि एक खराब कृषि वर्ष मेंज ब सूखा या बाढ़ आ जाए, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदा, या मानव निर्मित समस्याएँ जैसे– खाद्य बाजार में सट्टा बाजारी के दुष्प्रभाव से कीमते बढ़ने लगे, खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी के कारण पूर्ति की कृत्रिम बढ़ने लगे अथवा खाद्य वस्तुओं का जरूरत से अधिकनियमित कर दिया जाए और भौतिक रूप से इनकी कमी हो जाए। ये सभी खाद्य वस्तुओं की पूर्ति से जूड़ी समस्याएँ हैं जिसके कारण खाद्य असुरक्षा का खतरा हो सकता है। इसी तरह खाद्य वस्तुओं की मांग के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन नही होने से लोगों की वास्तविक आय का न बढ़ना और वास्तविक आय बढ़ भी रही है। लेकिन खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अधिक तेजी से वृद्धि हो रही हो तब भी खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो सकती है।

बाजार आधारित विनियम प्रणाली, जहाँ खाद्य वस्तुओं की कीमतें मॉग और पूर्ति पर आधारित होती हैं, खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यदि खाद्य वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाए या बाजार में इन वस्तुओं की जमाखोरी करने लगे या आर्थिक असमानता बढ़ने से कुछ लोग जो आर्थिक संसाधनों पर अधिकार जमा लेते हैं, बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अधिक उपभोग करने लगें तो भी इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और समाज के गरीब तबके के लोग प्रचलित कीमतों पर इन खाद्य वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में खाद्य असुरक्षा एक आम बात हो जाती है।

अतः इसके लिये आवश्यक है कि देश में खाद्य असुरक्षा और गरीबी हटाने के लिये नीति निर्धारण करते समय दो महत्वपूर्ण बातों पर अधिक जोर दिया जाए। प्रथम, देश में सामाजिक सुरक्षा उपायो के अंतर्गत तुरंत संरक्षण योजनाएँ चलाई जाएँ और कुपोषित बच्चों, गरीब महिलाओं, वृद्धों विकलांगों को जरूरी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। द्वितीय खाद्य सुरक्षा का दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करते हुए रोजगार सृजन, कीमत नियंत्रण और कृषिगत वृद्धि पर अधिक ध्यान देते हुए टिकाउ औद्योगिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए ताकि लोगों की आय और उपयोग को बढ़ाया जा सके।

खाद्यान्न उत्पादन

किसी भी देश में होने वाला कृषि उत्पादन विशेषकर अनाज उत्पादन उस देश की खाद्य सुरक्षा का एक प्रमुख आधार होता है। भारतीय कृषि आज भी मानसून पर आधारित हैं वर्ष 2008–09 में, जब खाद्य वस्तुओं का उत्पादन 234.47 मिलियन टन था, की तुलना में वर्ष 2009–10 में देश के कई भागों में सूखे के कारण खाद्य वस्तुओं का उत्पादन घटकर 218.11 मिलियन टन रह गया था जो कि पिछले दो वर्षों में मानसून के अच्छे होने के कारण खाद्य

वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि दर्ज की गई ओर यह वर्ष 2011–12 में बढ़कर 257.44 मिलियन टन हो गई।

खाद्य वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता में यह वृद्धि मुख्यतः उत्पादकता में वृद्धि के कारण आई है। ऑकड़े बताते हैं कि वप्र 1990–91 में 127.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होता था जो 2011–12 में घटकर 125.0 मिलियन हेक्टेयर रह गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13 के अनुसार खाद्य वस्तुओं की उत्पादकता में पिछले 20 वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई हैं वर्ष 1990 में खाद्य वस्तुओं की उत्पादकता 1,380 किग्रा, प्रति हेक्टेयर थी जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 2.059 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर हो गई थी। कृषि गत भूमि, जहाँ खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होता रहा है, उसका हस्तातरण अन्य कामों के लिये होने लगा है जेसे संरचनात्मक विकास। इसी तरह खेती की भूमि का हस्तांतरण खाद्य पदार्थों के उत्पादन से हटकर नकदी फसलों के उत्पादन की तरफ भी हुआ हैं उत्पादकता में यह वृद्धि कृषि कार्यों में प्रयोग की जाने वाली तकनीक में सुधार और अधिक उत्पादकता देने वाले बीच के उपयोग के कारण हुआ हैं परंतु यह पाया गया है कि इन तकनीकों के आवश्यकता से अधिक प्रयोग के कारण आज खेती की भूमि खासकर सघन खेती पाये क्षेत्रों में भूमि के अनुपजाऊ होने की समस्या पैदा हो गई हैं कृषि भूमि के बंजर होने के कारण खाद्य वस्तुओं की उत्पादकता वृद्धि दर में कमी आई है जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से शोचनीय है।

खाद्य वस्तुओं के मुल्य

देश में मूल्यां, विशेषकर खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण (2011–12) के अनुसार 2005–06 मेंखाद्य वस्तुओं के मूल्यों में 5–38 प्रतिशत 2008–09 में 9 प्रतिशत और 2010–11 (अप्रैल से जनवरी) के बीच 16.75 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 के अनुसार खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 2011–12 के दौरान 7.29 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही थी जो पुनः 2012–13 (जनवरी से सितंबर) के दौरान बढ़कर 9.22 प्रतिशत हो गई। इस पकार पिछले कुछ वर्षों में खाद्य वस्तुओं की महंगाई अधिक रही है। कीमतों में वृद्धि के कई कारण रहे है जिसमें सर्वप्रथम उदारीकरण के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्यों के उतार–चढ़ाव का सीधा अंसर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि से भारत का व्यापार घाटा जो 2009–10 में 109.62 मिलियन डालर था, से बढ़कर 2011–12 (अप्रैल से दिसंबर) में 133.27 मिलियन डॉलर हो गया। व्यापार घाटे में यह वृद्धि अनेक कारणों से हो सकती है। जैसे विदेशी वस्तुओं की माँग में वृद्धि, आपातित पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि इत्यादि व्यापार घाटों में वृद्धि का एक और कारण डालर के मुकाबले रूपये के मूल्य में पिछले दो साल में आई गिरावट भी है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत विस्टफोट और रूप्ये के अवमूल्यन का सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ा

जिसके कारण देश में मुद्रा स्थिति का चक्र उत्पन्न हुआ जिसमें प्राथमिक और अन्य खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई।

मुद्रा स्थिति के अनेक घरेलू कारण भी रहे है जैसे साख बाजार में व्यापारी अक्सर खाद्य पदाथों की जमाखोरी कर बाजार में कृत्रिम रूप से आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं और कीमतों में वृद्धि कर लाभ जनित मुद्रा स्फीति की स्थिति पैदा करते है। कृषि में पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक विनयोग के कम होने से कृषि संबंधी लागतों में वृद्धि हुई है।

रोजगार और खाद्य सुरक्षा

आर्थिक सर्वेक्षण (2011—12) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या जो 1991 मं 190.58 लाख थी 2010 में घअकर 178.62 लाख रह गई अर्थात् 1991 से 2010 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सृजन में 6.28 प्रतिशत की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान संगठित निजी क्षेत्र में रोजार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (N.S.S.O.) के चौसठवें दौर (2007—08) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में रोजगार वृद्धि दर मात्र 0.17 प्रतिशत थी। इसी तरह छ्रैैण्व्‌ के पैसठवें दौर (2009—10) सर्वेक्षण के अनुसार संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर 1983 से 1993—1994 के बीच 1.2 प्रतिशत प्रतिशत रही। लेकिन 1994 से 2009 के बीच यह दर घटकर मात्र 0.03 प्रतिशत रह गई। रोजगार वृद्धि की यह दर देश में चार दशक के दौरान उपलबध सभी दर्ज आकड़ों में न्यूनतम थी। स्पष्ट है कि पिछले दो दशकों में विकास की दर तो बढ़ी परंतु सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार लगातार कमी आई हैं। देश का असंगठित क्षेत्र, जहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या का जगभग 94 भाग करता है, देयनीय दशा से गुजर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर में कमी और कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या के भारी दबाव के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार आय के संकेंद्रण अर्थात आर्थिक असमानता बढने के कारण भी दे‌ा के निर्धन वर्ग में खाद्य सुरक्षा की समस्या गंभीर हुई। अतः आवश्यक है कि इस एक बड़े वर्ग को ध्यान में रखकर खाद्य सूरक्षा कानून बनाए जाए।

निष्कर्ष

तमाम चुनौतियों के बीच सभी नागरिकों के लिये खाद्यसुरक्षा का लक्ष्य आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 85 करोड़ से अधिक आबादी भुखमरी व कुपोषण से ग्रस्त है। यह हम सभी के लिये शर्म की बात है कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा भूख से तड़प रहा है जबकि हम पहले से अधिक अनाज पैदा रहे हैं।

आज देश में एक दीर्घकालिन समग्र आर्थिक नीति की आवश्यकता है जो देश के गरीब, भमिहीन और देश की विशाल असंगठित क्षेत्र को ध्यान मे रखकर बनाई जाए ताकि विकास के विश्व सहसृष्टि लक्ष्यों को समय रहते प्राप्त किया जा सके।

इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिये देश में प्रत्येक नागरिक को भोजन का अधिकार दिया जाय जेसे कि नई खाद्य सुरक्षा कानून जो कि देश के 67 प्रतिशत लोगों (जिनमें 75 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों और 50 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रो से सुने जाऍगें) के लिये प्रति व्यक्ति प्रति माह एक निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराएगा ताकि दकेश में एक भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित नर है। इस संदर्भ में देश में रोजगारपरक योजनाएं लागू करनें कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने और भूमि सुधार कार्यक्रम का पूर्णतः लागू करने के लिए भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भारत से भुखमरी, कुपोषण व गरीबी को सदा के लिये समाप्त किया जा सके।

संदर्भ सूची

- लाल एवं लाल – आर्थिक विकास, आयोजन तथा पर्यावरण, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
- भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रकाशन– प्रतियोगिता साहित्य सीरीज 2005।
- भारतीय अर्थव्यवस्था, उपकार प्रकाशन 2013।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13।
- लाल एवं लाल– आर्थिक सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
- मिश्रा एवं पुरी– भारतीय अर्थव्यवस्था,
- एस0पी0सिंह– आर्थिक विकास एवं नियोजन एस0चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड रामनगर, नई दिल्ली।
- 'योजना' मार्च 2013
- 'योजना' दिसम्बर 2013।